

[श्री टी० एस० नेगी]

लित हैं, को सरकार ने जनजाति क्षेत्र बहुरन वर्षों पहले घोषित किया था । वहां की जनता को वैसे काफी लाभ भी हुआ, क्षेत्र की तरक्की हुयी इसी प्रकार से टेहरी गढ़वाल जिले का जौ पुर क्षेत्र एवं उत्तरकाशी जिले का रवाई क्षेत्र जिसमें पुरौला नौगांव एवं मोरी ब्लाक सम्मिलित हैं, को भी जन-जाति क्षेत्र घोषित किया जाय । इसमें उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा । इस जन-जाति क्षेत्र का मुख्यालय क्षेत्र के मध्य में होना चाहिये था जिससे लोगों को सम्पर्क की सुविधा हो ।

रवाई जौनपुर क्षेत्र प्रदेश में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । सामन्ती व्यवस्था में भी इस क्षेत्र की उपेक्षा ही होती रही । फलस्वरूप सन् 1930 में रवाई कान्ड हुआ जिसमें सैकड़ों व्यक्ति शहीद हुये, तानाशाही की गोली के शिकार हुये । आज भी वहां के लोगों को जन-जाति क्षेत्र की पूरी सुविधा न मिलने के कारण एवं उनकी जायज मांगों की अन्वहेलना होने की वजह से वहां आन्दोलन का वातावरण बन चुका है । वहाँ के नाजवान अपनी मांगों के लिए हर जायज तरीके से आन्दोलन करेंगे और जब तक उनकी मुनवायी न हो जाये और उनकी जायज मांगें पूरी न हो जायें यानी जौनपुर एवं रवाई को उसी के साथ लगे हुए जौनसार एवं वावर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती (जो एक ही जन जाति क्षेत्र के अंग हैं) तब तक वहां की जनता संघर्ष रत रहेगी । इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जन-जातियों में असंतोष का वातावरण पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है । क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जन-जातियों के उत्थान और विकास का काम नहीं हो रहा है । इन जन-

जातियों के उत्थान की जिम्मेदारी न केवल राज्य सरकार की है, बल्कि केन्द्र सरकार की भी है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ खींचते हुए प्रार्थना करता हूँ कि इस दिशा में प्रभावशाली कदम शीघ्रता से उठाये जायें ।

(ii) EVASION OF DUTY ON STAINLESS STEEL

SHRI CHINTAMANI JENA (Batasore): The stainless steel re-rollers in the country are very much perturbed over the recent phenomenon of large quantities of stainless steel sheets being dumped in the country by dubious means. Besides putting the indigenous industry out of gear these imports have been depriving the Government of its legitimate revenue in form of import duty.

It is stated that large quantities of cold rolled stainless sheets totalling over 2,500 tonnes have already been brought in the country in the form of folded angles and in the process the Government lost about Rs. 11 crores. If no action is taken to remove the loophole in the import policy, which makes this business possible, another shipment of 7,000 tonnes is expected to arrive and dump the goods in Indian shores, putting the Government to a further loss of Rs. 30 crores.

The modus operandi of the whole scheme is like this: According to the import policy for the year 1980-82, the stainless steel sheets are canalised for imports through the MMTTC and the customs duty payable on these sheets is 220 per cent plus 30 per cent auxiliary and Rs. 363 per tonne CVD. These sheets, however, can be brought here under OGL if they are imported by "actual users" in the form of folded angles and circles with the current customs duty of 60 per cent plus 25 per cent auxiliary plus Rs. 363 per tonne CVD. Prior to the budget of 1982-83, the duty was only 35 per cent plus 10 per cent Rs. 363 per

tonne CVD. Thus, on every tonne of stainless steel sheets imported as angles for circles, the exchequer loses about Rs. 40,000 in the form of duty besides the foreign exchange cost of Rs. 222,000 per tonne.

The indigenous industry circles point out that the Government is expected to lose over Rs. 200 crores in customs duties alone, besides the outflow of foreign exchange of over Rs. 100 crores if the loopholes are not plugged by suitable amendments to the customs tariff Act and the Import policy.

The Government apathy in this connection would only aggravate the plight of the languishing domestic stainless steel producers, it is feared.

In these circumstances I would request the Government to kindly take up this problem with right earnest so that not only the small business men, lakhs and lakhs of middle class and lower middle class people of the country who are the regular users of stainless steel will be able to redress their difficulties.

(iii) EXTENSION OF SITAPUR—MILANI RAILWAY LINE UPTO DUDHUWA.

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्याधिक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ ।

मेरा लोक-सभा क्षेत्र खेरी लखीमपुर यों तो पहले ही काफी पिछड़ा हुआ है और गरीब लोगों के लिए काफी समस्याएं अभी हैं, तो भी एक समस्या जो इस समय उग्र रूप धारण किए हुए है, वह है कि जो गाड़ी पहले सीतापुर से दुधुवा स्टेशन पर चलती थी, उसको अब सिर्फ मिलानी स्टेशन तक ही चलाया जा रहा है । इसके अलावा इस क्षेत्र को अन्य रेल सेवाओं से भी वंचित करने की खबर है ।

सीतापुर से दुधुवा रेल सेवा जो कि हजारों लोगों के लिये सुविधा का साधन है, उसको तुरन्त चालू किया जाना चाहिए । इस रेल सेवा से ये लोग रोजाना मिलानी से दुधुवा आते-जाते हैं । इन दोनों जगहों का इस रेल सेवा से तुरन्त मि करना आवश्यक है, क्योंकि लोग अलान बैगरहा इसी गाड़ी से पहुंचते थे । इस गाड़ी के कैंसिल करने से अब समस्या बहुत गम्भीर हो गई है ।

मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि वे तुरन्त सीतापुर—मिलानी रेल सेवा को दुधुवा तक जाने का आदेश दें ।

(iv) EXTENSION OF T.V. NETWORK THROUGHOUT THE COUNTRY

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Under Rule 377, I wish to bring to the attention of the House the subject of setting up of Television Transmitters in the country.

It needs no argument to prove that there is powerful impact of television on people's ideas and opinions. It is one of the most effective forms of mass media to educate public opinion. In India, where a fairly large percentage of population is still illiterate, television can play a vital role in enlisting the voluntary and active cooperation of the common man for nation-building projects, such as Family Planning. In view of its immense educative possibilities, the extension of the television network throughout the country should be one of the top priorities of the Government. And, with the launching of INSAT, this no longer remains merely a Utopian goal.

At the moment, only 16 per cent of the country's population is covered by Television. The Sixth Five-year Plan has envisaged increasing it to 33 per cent by the end of March, 1985 and has allocated Rs. 87 crores for setting up regional Television Stations.